जौद्योगिक विकास तथा समबाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमव): (क) और (ख). अन्य विभागों/कार्यालयों की भांति ही दिल्ली प्रशासन के एक कर्मचारी को भी जो दिल्ली नगर निगम में नगर-पाल के निजी सचिव के पद पर प्रतिन्वृद्धित पर था और जो 350-900 रु० (तथा 75 रु० मासिक विशेष वेतन) के वेतन कम में या, औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति में सहायक निदेशक के पद पर उसकी इसलिये नियुद्धित की गई कि पिछले प्रशासनिक अनुभव एवं योग्यता की दृष्टि से वह इस पद के लिये विशेष रूप से उपयुक्त पाया गया।

भारत हैवी प्लेट्स एण्ड बैसल्स कारपोरेशन

1993. श्रीलखणलाल कपूरः श्रीरामचरणः

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या "भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स कारपोरेशन" के प्रबन्ध निदेशक के पद पर कोई नई नियुक्ति की जा रही है; और
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्रीकडरहीन अली अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वाणिज्य मंत्रालय में इन्बेस्टीगेटर्स 1994. श्री लखण लाल कपूर : श्री राम चरण :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय में इन्वेस्टीगेटर्स के कितने पद हैं ;

- (ख) उनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित किये गये हैं; और
- (ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति इन पदों पर वास्तव में काम कर रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (भी मौहम्मद शक्री कुरेशी) : (क) 69।

(ख) और (ग). वाणिज्य मंत्रालय में इन्वेस्टीगेटर के पदों की भर्ती के नियमों के अनुसार 50 प्रतिशत पद प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण द्वारा भरे जाते हैं। आरक्षण आदेश प्रत्यक्ष भर्ती परिणामतः के लिए आरक्षित रिक्तियों पर ही लागू होंगे। साम्प्रदायिक सूची (कम्यूनल रौस्टर) बनाने के प्रयोजनार्थ इन्वेस्टीगेटर्स के पदों को मंत्रालय में श्रेणी-3 के अन्य समवर्ती पदों के ग्रुप में शामिल कर लिया गया है। अतः इन्वेस्टीगेटर्स के ग्रेड में कोई अलग आरक्षण नहीं है परन्तु ग्रुप में नियुक्तियां समग्रतः निर्धारित सूची (रौस्टर) के आधार पर की जाती हैं। इस समय मंत्रालय में अनु-सूचित जातियों के चार तथा अनुसूचित आदिम जातियों का एक व्यक्ति इन्वेस्टीगेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं।

उद्योग व्यापार पत्रिका

1995. श्रीलखण लाल क्यूर: श्रीराम चरण:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा हिन्दी में "उद्योग व्यापार पत्निका" नामक पत्निका प्रकाशित की जाती थी ;
- (ख) इस पत्रिका का प्रकाशन बन्द किये जाने के क्याकारण हैं;और

(ग) क्या सरकार का विचार इसका अकाशन पून: आरम्भ करने काहै?

वाणिक्य मंत्रालय में उत्यंत्री (श्री मुहम्मद शक्ती कुरैशी): (क) जी, हाँ।

(ख) सितम्बर 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण के परिणामस्वरूप उत्पन्न परिस्थि- शित्यों में मितव्ययता के उपाय के रूप में इसका अकाशन बन्द कर दिया गया था।

(ग) जी, हां।

अखिल भारतीय हम करघा बोर्ड

1996. श्रीलखणलाल कपूर: श्रीराम चरण:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या उचित भारतीय हथकरघा बोडं को एक कानूनी आयोग का रूप देने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और
- (ख) यदि हां, तो संसद् में इस आशय का विधेयक कब पुर:स्थापित होने की संभावना है ?

बाणिज्य मंत्रात्रय में उपमंत्री (श्री मुद्दम्बद शक्तो कुर्दशी): (क) और (ग). अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के भावी गठन के संबंध में विचार हो रहा है।

ENCOUNTER AT DUM DUM RAILWAY STATION

1997. SHRI KAMESHWAR SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that an Officer of Railway Protection Force was killed in an encounter at Dum Dum Railway Station on the 16th November, 1967;
- (b) whether any enquiry was held into the matter; and
 - (c) if so, the findings thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) Yes.

(b) and (c). Yes, Government Railway Police, Sealdah have registered a case on Crime No. 56 dated 16-11-67 under sections 147, 148, 149, 324, 353, 307, 302 I.P.C. and 6(3) Indian Explosives Act and the Police investigations are still in progress.

THROUGH BOGIE FROM ROURKELA TO PURI

1998. SHRI S. KUNDU: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether Government are aware of the demand of the Railway Users' Committee of Rourkela to provide one through bogie from Rourkela to Puri to be attached to some train at Rourkela station;
- (b) if so, when Government propose to provide a bogie; and
 - (c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) Yes.

(b) and (c). This is under examination.

DIATARI IRON ORE PROJECT

1999. SHRI S. KUNDU: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3607, on the 8th December, 1967 and state:

- (a) whether Government are aware that the Diatari iron ore project is passing through financial difficulties;
- (b) whether the target of export of iron ore has been achieved;
- (c) whether the Orissa Mining Corporation or Orissa Government have sought the assistance of the Central Government or the National Mineral Development Corporation to tide over the present financial and other difficulties facing Diutari Iron Ore Project in Orissa; and
- (d) whether Government have suggested any plans to come to the rescue of Diatari Iron Ore Project?